लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 16 - 30 अप्रैल 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक - 64

"जिस श्रम से आनंद प्राप्त हो वह अमृत के समान है। वेदना की निवृति है।

: शेक्सपियर

सिकंदरपुर जल निकाय का सौंदर्यीकरण

3

ख़राब फसलों का मिलेगा मुआवजा

6

आतिथ्य सत्कार से जीता विदेशी मेहमानों का दिल

7

जन संवाद

ग्रामीणों से सीएम की सीधी बात

मनोज प्रभाकर

विकास की कोई सीमा नहीं होती, यह एक सतत प्रक्रिया है। किसी भी क्षेत्र की खुशहाली के लिए ढांचागत विकास के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति निहायत जरूरी है। हरियाणा प्रदेश में यह सब सहजता से हो रहा है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से बागडोर संभाली है राज्य के हर पहलू को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई कोना उपेक्षित न रह जाए इस पर विशेष ध्यान है। कहते हैं कर्मक्षेत्र में कोई पूर्वाग्रह न हो तो उसके पणिाम सदैव सुखद होते हैं। 'मनोहर काल' में यह सब देखा जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि बिना भेदभाव के हो रहे विकास कार्यों से लोगों में सामाजिक सौहार्द स्वतः निर्मित हो रहा है। क्षेत्रवाद, जातिवाद या अन्य किसी वाद पर अब चर्चा नहीं होती।

कोई परिवार गरीब न रहे, युवाओं को रोजगार मिले, हर खेत को पानी मिले, लोगों का जीवन सहज व सरल हो इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में निरंतर प्रयास जारी हैं।

इन सबके बावजूद लोगों के मन में ऐसी कोई बात न रह जाए जिसे सत्तापक्ष के साथ साझा करने की जरूरत हो, के लिए मुख्यमंत्री स्वयं लोगों के बीच जा रहे हैं, और उनसे संवाद कर रहे हैं।

'जन संवाद' कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के सम्मानित लोग भी मौके का फायदा उठा रहे हैं। वे सीएम के सामने बिना लाग लपेट के अपनी समस्याएं व मांगें रख रहे हैं। कहते हैं 'आपणे सीएम तैं बात करण का मौका मिल्या सै तो जरूर करैंगे, और खुलकै करैंगे।'

मुख्यमंत्री भी प्रोटोकोल से समझौता करते हुए लोगों के बीच विराजमान होते हैं और उनके मन की बात सुनते हैं। वे अधिकांश समस्याओं का मौके पर निवारण कर रहे हैं। जायज मांगों को मूर्तरूप देने के लिए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। स्थानीय लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस आत्मीय स्वभाव से काफी प्रभावित हैं।

मुख्यमंत्री ऐसे समय में लोगों के बीच जा रहे हैं जब नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतें अपने-अपने गांव के विकास की योजनाएं बना रही हैं। पढ़ी-लिखी पंचायतें पूरे उत्साह के साथ मुख्यमंत्री से अपनी योजनाएं साझा कर रही हैं। महिला जनप्रतिनिधियों को खूब सम्मान मिल रहा है तथा उनकी बातें सुनी जा रही हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता संभालते ही प्रदेश की राजनीति की दशा व दिशा बदलने का संकल्प लिया था। लोगों की शिकायतों व उनकी समस्याओं के निदान के लिए अनेक नए प्रकल्पों को लागू किया।

रोहतक जिले से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री ने सिरसा, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र व फतेहाबाद जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किये जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निवारण किया।

मुख्यमंत्री का अगला जनसंवाद कार्यक्रम पलवल जिले में हुआ। इसके बाद वे पानीपत, करनाल व हिसार जिलों के ग्रामीणों से संवाद करेंगे। सभी 22 जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम रखे गए हैं। कार्यक्रमों में ऑनलाइन सेवाओं के अलावा पेयजल, सिंचाई जल, गांव के मुख्य मार्ग व गलियों के निर्माण संबंधी मांगें लोगों की ओर से आ रही हैं।

ई टेंडरिंग मामले में लोगों से खूब बातचीत हुई। पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से कहा कि विकास कार्यों की पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लाई गई यह नीति सही है। इससे न केवल पैसे की बचत होगी, कार्य भी समय पर होंगे। विरोध करने का इसमें कोई तुक नहीं है।

G20 भारत 2023 INDIA

पेंशन की अर्हता तीन लाख सालाना

वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन व विधवा पेंशन 250 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 2750 रुपए की गई है। जिन बुजुर्गों की सालाना आय तीन लाख रुपए तक है उनको भी इस लाभ का पात्र माना गया है। अभी तक यह अर्हता दो लाख रुपए सालाना थी।

राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान किए गए वादे को भी निभाया है।

पहली अप्रैल से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, यानी मई माह में जो पेंशन मिलेगी वह 2750 रुपए मिलेगी। पेंशन के लिए बजट में 1300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

बता दें प्रदेश में 2022 में 17.45 लाख बुजुर्गों को 2500 रुपए मासिक पेंशन दी जाती रही है। तब राज्य के खजाने पर 5234 करोड़ रुपए का बोझ था। तीन वर्षों के आंकड़ों की बात करें तो हर माह अमूमन 12 हजार बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन से जोड़ा गया है।

2.30 लाख परिवारों के दोबारा बनाये राशन कार्ड

परिवार पहचान पत्र में आय से संबंधित त्रुटियों के कारण जिन परिवारों के राशन कार्ड कट गए थे, उनमें से 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बनाये गए हैं।

शिकायतें रहती थीं कि पात्र परिवारों के राशन कार्ड नहीं बने हैं जबकि बहुत से अपात्र यानी साधन संपन्न परिवार योजनाओं का निरंतर लाभ ले रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने एक नया प्रयोग करते हुए प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाया। कई टीमें लगाकर परिवारों का सर्वे कराया गया। इतना ही नहीं, पहले बीपीएल की जो आय पात्रता सीमा एक लाख 20 हजार रुपए वार्षिक थी, बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपए किया गया। इन सब प्रक्रियाओं के बाद परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की। जनवरी माह में लगभग साढ़े 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए। राज्य सरकार ने खाकी राशन कार्ड यानी ओपीएच श्रेणी को समाप्त कर बीपीएल कार्ड की श्रेणी में जोड़ा है। इसका परिणाम यह हुआ कि अब केवल पात्र परिवारों को ही सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि धीरे-धीरे यह भी ध्यान में आया कि कुछ परिवार जो पहले बीपीएल श्रेणी में थे, वे परिवार संपन्न हो गए। कुछ परिवार ऐसे मिले, जिनके परिवार में किसी न किसी सदस्य को नौकरी मिल गई और कुछ परिवारों ने पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरी है तथा इनकम टैक्स का भुगतान किया है। इस प्रक्रिया के बाद शिकायतें प्राप्त हुई कि उनका राशन कार्ड गलत कट गया है। इस समस्या के समाधान के लिए जनवरी, 2023 में ही नागरिकों से पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाने का अनुरोध किया गया। शिकायतें प्राप्त होने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके लगभग 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बनाये गए व उन्हें जनवरी माह का राशन मुहैया कराया गया। यह संभव इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार की नीति और नीयत साफ है। सरकार की पारदर्शी नीति से पात्र नागरिक को योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

लाभार्थियों ने सीएम का धन्यवाद करते हुए कहा कि शिकायत दर्ज करवाने के बाद जिस गति से राशन कार्ड दोबारा बनाये गए, उससे स्पष्ट हो गया कि सरकार की नागरिकों के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता सौ की सौ है। लगने लगा है कि गरीब परिवारों की चिंता अब चिंता नहीं रह गई है।

- संवाद ब्यूरो

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार गरीब व जरूरतमंदों की सरकार है। हम उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इनका सरकार पर पहला हक है। प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर है या संपन्नता की ओर अग्रसर हैं, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी योजनाओं के लाभ को छोड़ने का प्रयास करें, ताकि जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।

संपादकीय

सेहत को प्राथमिकता

कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के हर जिले में आरटीपीसीआर लैब लगाई गई है। संभवतः हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां हर जिले में आरटीपीसीआर लैब है। जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी मशीनें लगाई गई हैं। पहले जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था।

कोरोना के नए रूप से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सभी लोगों से ऐहतियात बरतने के लिए कहा है। राज्य सरकार चाहती है कि लोग बिना किसी व्यवधान के अपने काम करें और कोरोना के साथ लड़ाई जारी रखें। स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि 100 से ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों में लोग मास्क लगाकर रखें। स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक रूप से मास्क लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस बार का वेरिएंट बहुत ही माइल्ड है और इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं है। कोरोना के समय स्वास्थ्य केंद्रों में जो भी सेवाएं थी उनको दोबारा एक्टिव कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस सेवा 108 व पुलिस की सेवा 112 को अलर्ट किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी नागरिक को तत्काल सुविधा मिल सकें।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आरंभ से ही सेहत विभाग को चुस्त दुरुस्त रखने का प्रयास किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के साढ़े 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू की और आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है।

प्रदेश सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना बनाई है। इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अभी तक साढ़े 4 लाख लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। सभी अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी पर स्वास्थ्य परिक्षण किया जा रहा है। आने वाले समय में निजी अस्पतालों, लेबोरेट्री के साथ समझौता किया जाएगा, ताकि नागरिकों के टेस्ट जल्द किए जा सकें। इससे किसी भी बिमारी का पता पहले ही लग जाएगा और उसका ईलाज समय पर किया जा सकेगा।

-डा. चंद्र त्रिखा

उपहार योजना से मिले एक करोड़ 14 लाख

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक और स्वस्थ पहलकदमी की है। अपनी प्रयोगधर्मी नई सोच के तहत आरंभ की गई मुख्यमंत्री-उपहार योजना का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है।

मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन में सादगी का एक ओर उदाहरण पेश करते हुए उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में सामाजिक संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा सम्मान स्वरूप प्राप्त उपहारों को समाज भलाई में लगाने का निर्णय लिया था। पहले चरण में 51 उपहारों के लिए लोगों ने एक करोड़ 14 लाख 95 हजार रुपए की सहयोग राशि दी।

मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उपहार वितरण समारोह में सहयोग देने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने सम्मान सहित ये उपहार वितरित किए। इस अवसर पर मनोहर लाल ने उपहार प्राप्त करने वाले लोगो को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इन उपहारों से प्राप्त सहयोग राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जा किया गया है और इसे जनकल्याण के कार्यों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने उपहार प्राप्त करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के प्रबुद्ध लोगों को समाज सेवा के भाव से जनकल्याण के लिए जोडने हेतु यह पहल आरंभ की गई। आप सभी का साभार जिन्होंने इस पहले में सहयोग किया।

मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है और जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सीएमओ व एक अन्य अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी उनके पास सहायता के लिए आए आवेदनों पर निर्णय लेकर एक निश्चित राशि वितरित करती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय कल्याण की विचारधारा से प्रेरित होकर हरियाणा में भी प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रही है।

सूचना विभाग को सुशासन पुरस्कार

हरियाणा का सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग सही मायनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के डिजिटल एवं सुशासन विजन को साकार कर रहा है। विभाग निरंतर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सही जानकारी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक सफलतापूर्वक पहुंचा रहा है।

विभाग का प्रेस अनुभाग तथा डिजिटल मीडिया सेक्शन सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और फ़र्जी ख़बरों पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। डिजिटल मीडिया सेक्शन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रेरक नेतृत्व तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल और महानिदेशक डॉ. अमित कुमार अग्रवाल के सक्षम और निरंतर मार्गदर्शन में काम कर रहा है। फैक्ट चेक अकाउंट्स के लिए डिजिटल मीडिया सेक्शन को सुशासन पुरस्कार से नवाज़ा गया।

इसी कड़ी में विभाग ने एक और ऊंची छलांग लगाते हुए 25 मार्च, 2023 को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ़ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विज्ञापनों से संबंधित रिलीज़ आर्डर एवं बिलिंग सिस्टम प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। प्रोजेक्ट कैटेगरी के तहत दिए गए इस अवॉर्ड को विभाग की ओर से उपनिदेशक उर्वशी रंगारा ने प्राप्त किया।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से ऑनलाइन की यह प्रक्रिया आरंभ करने वाला हरियाणा का सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग शायद देश का ऐसा पहला विभाग है जिसने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी योजनाओं के विज्ञापन जारी करने के लिए ऑनलाइन रिलीजिंग आर्डर व बिलिंग सिस्टम आरंभ किया है। इससे विज्ञापन दरों में समानता के साथ-साथ पारदर्शिता आई है। इस प्रणाली से त्वरित भुगतान भी सुनिश्चित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने विभाग के इन प्रयासों की न केवल सराहना की है बल्कि दूसरे विभागों को भी डिजिटलाइजेशन को अपनाने के निर्देश दिए हैं ताकि नागरिकों को सरकार की योजनाओं की सही जानकारी उपलब्ध हो सके।

बतादें विभागीय विंग डिजिटल मीडिया की ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 11 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली उपस्थिति है।

-संवाद ब्यूरो

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

पदमा में स्थापित होगा वेंचर कैपिटल फंड

वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत युवा बन सकेंगे इंटरप्रेन्योर

हरियाणा सरकार द्वारा स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा उद्यमियों की तरह 'पदमा' (प्रोग्राम टू एक्सीलेरेट डिवलेपमैंट फॉर एमएसएमई एडवान्समेंट) में भी वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा ताकि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत अधिक से अधिक युवा इंटरप्रेन्योर बन सकें। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने 'पदमा' को लागू करने के लिए रणनीति बनाई है और उसमें सुधार के लिए कई अहम सुझाव भी दिए।

योजना के उद्देश्य

हरियाणा सरकार ने सभी वर्ग के युवाओं के लिए पदमा योजना शुरू की है, सरकार की यह पदमा योजना से बेरोज़गार उम्मीदवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने या एक उद्यम स्थापित करने, स्वयं रोज़गार बनाने और अन्य बेरोज़गारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने में सक्षम बनाने में मदद करेगी। यह पदमा योजना उद्यमियों को काफ़ी हद तक लाभान्वित करेगी और उन्हें व्यवसायी में बदल देगी। जिस प्रकार से बजट में राज्य सरकार ने युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 5 करोड़ रुपए तक के

> पदमा योजना के तहत, राज्य सरकार नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ओर रोज़गार के नए अवसर प्रदान करने के लिए लागू की हुई है। यह योजना नए उद्यमों को स्थापित करने में के सभी योग्य सदस्यों को सक्षम करेगी।
>
> **-दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री**

200 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना बनाई है, ठीक इसी प्रकार 'पदमा' के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भी वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।

सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा

प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की 'पदमा' योजना के तहत 'वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट' पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य कलस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देना है। हाल ही में पेश किए गए बजट में भी अगले पांच वर्षों में 'पदमा' के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं जिससे डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जैसे नए इनोवेटिव इंसेंटिव पेश किए जाएंगे।

युवाओं को मिलेगा इन्सेंटिव

जहां युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा अपेक्षित कौशल, व्यक्तित्व और संचार कौशल के साथ युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, वहीं 'पदमा' के तहत विशेषकर ग्रामीण युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। 'पदमा' के तहत उद्योग लगाने हेतु करीब दो दर्जन स्थानों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही बाकी ब्लॉक में जगहों को अंतिम रूप देकर लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 'पदमा' के लिए छह योजनाएं बनाने की योजना तैयार की गई है जिसमें विभिन्न इन्सेंटिव इत्यादि देने का प्रावधान किया जाएगा।

-संवाद ब्यूरो

मुख्यमंत्री ने संत कबीर कुटीर से जनसंवाद पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री को नागरिकों द्वारा अपनी समस्याओं व शिकायतों की लिखित में दी गई जानकारी अब इस पोर्टल पर दर्ज होगी।

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब से डायल 112 को शुरू किया गया है तब से अपराध में कमी आई है। आठ मिनट में पुलिस की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच जाती है और आवश्यक कार्रवाई करती है।

मंत्रिमंडल के अहम फैसले

जनकल्याणकारी नीतियों को गति देने के लिए सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 36 कार्यों की सूची रखी गई जिनमें 33 महत्वपूर्ण कार्यों को अंतिम रूप दे दिया गया।

आयुष चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के तहत आयुष उपचार को भी शामिल किया है। चूंकि इन लाभार्थियों में से अधिकांश आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन सूचीबद्ध आयुष अस्पताल नहीं होने के कारण उन्हें अपने बिलों की प्रतिपूर्ति करवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।

नीति के अनुसार, सभी सरकारी आयुष संस्थान, निजी आयुष अस्पताल, जिनके पास एनएबीएच प्रमाणपत्र और प्रवेश स्तर के एनएबीएच प्रमाणपत्र हैं, को सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे आयुष निजी चिकित्सकों को बढ़ावा मिलेगा।

निश्चित पैकेज दरों को आयुष की सभी धाराओं अर्थात आयुर्वेद (96 पैकेज), योग (27 पैकेज) और प्राकृतिक चिकित्सा (30 पैकेज), यूनानी (85 पैकेज), और सिद्ध (49 पैकेज) में परिभाषित किया गया है।

सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी

राज्य सरकार ने गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, गुरुग्राम, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, फरीदाबाद और पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंचकूला की तर्ज पर सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सोनीपत की स्थापना करने का फैसला किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया के निरंतर, निरंतर और संतुलित विकास के लिए एक दृष्टि विकसित करना है। प्राधिकरण द्वारा शहरी सुविधा और ढांचागत विकास को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

रोजगार सृजन सब्सिडी में बढ़ोतरी

स्थानीय युवाओं में निवेश के प्रति आकर्षण की भावना को बढावा देने व रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति के तहत कर्मचारी रोजगार सृजन सब्सिडी 36000 से 48,000 रुपए तक तय करने का निर्णय लिया गया है। यह सब्सिडी बी, सी व डी ब्लॉक में हर साल हर कर्मचारी के लिए 10 साल तक लागू होगी।

स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा

राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त विद्यालयों कर्मचारियों को 9 अगस्त, 2017 को अधिसूचित हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम, 2017 के तहत अपने अधीन ले लिया था। उनकी पेंशन हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल नियम, 2001 के तहत दी गई थी।

पर्यावरण के अनुकूल कॉलोनी बनाने की योजना

कम घनत्व वाली पर्यावरण के अनुकूल कॉलोनियों को योजना अनुसार विकसित करने व लाइसेंस प्रदान करने के लिए नीति में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कॉलोनियों की स्थापना के लिए हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन में 25 एकड़, मध्यम जोन में 15 एकड़ और कम क्षमता वाले जोन में 10 एकड़ न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी। कॉलोनी में कोई भी अन्दर की सड़क 9 मीटर से कम चैड़ाई की नहीं होगी। ऐसी कॉलोनी में कम से कम एक एकड़ से 2.5 एकड़ तक एक प्लाट की ही अनुमति होगी। इनमें लोगों तक आसान पहुंच के लिए कम से कम 12 मीटर चौड़े रास्ते/ सड़क सुलभ होना चाहिए।

कॉलोनाइजरों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण

बकाया लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क और उस पर लागू ब्याज जमा करने में चूक करने वाले कॉलोनाइजरों को राहत देते हुए हरियाणा ने अपनी तरह की एक और एकमुश्त समाधान योजना 'विवादों का समाधान' की शुरुआत की है। यह योजना इसकी अधिसूचना से छह महीने की अवधि के लिए खुली रहेगी।

गौशालाओं के लिए जमीन

गौशाला, बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने वाली इच्छुक सामाजिक सोसायटी या धार्मिक संस्थाएं तथा चारे को उगाने के लिए अब शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ले सकेंगी।

शामलात देह में किसी भी भूमि को गौशाला निर्माण के उपरान्त प्रति 100 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु)के लिए 0.75 एकड़ के अनुपात में गौशाला की स्थापना हेतु पट्टे पर देने की अनुमति दी जायेगी।

गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण

राज्य सरकार ने वित्त विभाग में शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित करने, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने और बढ़ाने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की है। प्राधिकरण गुणवत्ता आश्वासन के लिए 1+4 स्तरीय प्रक्रिया अपनाएगा।

प्राधिकरण में अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार में सचिव के रैंक का या समकक्ष अधिकारी है या रहा है अथवा केंद्र या राज्य सरकार में इंजीनियर-इन-चीफ है या ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रतिष्ठित संस्थान में गुणवत्ता प्रबंधन या सरकार में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव है, वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्राधिकरण इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता और उसके प्रबंधन के लिए मानदंड और मानक स्थापित करेगा और अधिसूचित करेगा।

प्रमाणीकरण सेवा अनिवार्य

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग onetimeregn.haryana.gov.in पोर्टल पर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया।

- संवाद ब्यूरो

सिकंदरपुर जल निकाय का सौंदर्यीकरण

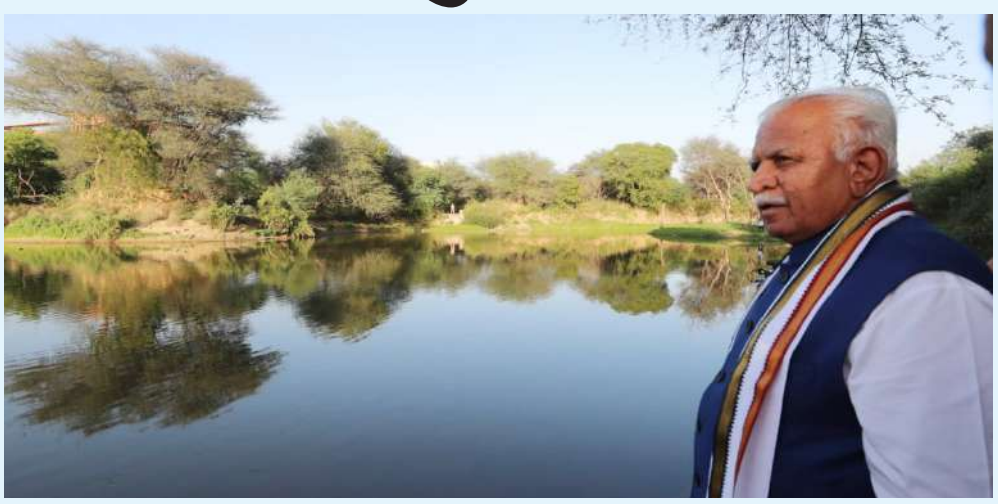

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं नामतः बसई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक रेलवे ओवर ब्रिज तथा सिकंदरपुर जल निकाय के कायाकल्प एवं सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के धरातल पर साकार होने से गुरुग्राम जिला में ढांचागत तंत्र को विस्तार मिला है। मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में इन दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मनोहर लाल ने कहा कि बसई में नवनिर्मित रेलवे ओवर ब्रिज, आने वाले समय में हीरो-होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे और आसपास के सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा साथ ही गुरुग्राम-झज्जर मार्ग पर पुराने आरओबी पर यातायात के दबाव को कम करेगा। गुरुग्राम में करीब 114 करोड़ रुपए की लागत से उमंग भारद्वाज चौक से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड (एनपीआर) को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा इस फोर लेन आरओबी की लंबाई 910 मीटर है और इसके निर्माण पर 23 करोड़ रुपए की लागत आई है।

मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर के समीप 90 एकड़ क्षेत्र में विकसित जल निकाय के कायाकल्प व सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस जल निकाय क्षेत्र को बहाल करने के लिए, अप्रैल 2019 में जीएमडीए और गैर सरकारी संस्था आईएम गुरुग्राम के बीच एक एमओयू हुआ था। इस जल निकाय के कायाकल्प पर 9.1 करोड़ रुपए की लागत आई। जिससे शहरों में व्यापक हरित रणनीति के तहत वन क्षेत्र को बढ़ावा मिला और पुराने जल निकाय को पुनर्जीवित किया गया।

करीब 90 एकड़ में फैले सिकंदरपुर जलाशय और वाटरशेड क्षेत्र के पर्यावरण-पुनर्स्थापना का मुख्य उद्देश्य गुरुग्राम के निवासियों को स्वच्छ और हरित वातावरण उपलब्ध कराना है। इस क्षेत्र में देसी प्रजातियों के वृक्षारोपण के माध्यम से शहर के शहरी हरित आवरण को बढ़ाना है।

'मनुष्य तू बड़ा महान है'

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम शहर की दो महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर साकार होते देखने के अवसर पर 'मनुष्य तू बड़ा महान है' गीत के बोल से अपना संबोधन आरम्भ किया।

उन्होंने मंच से गीत के बोल गुनगुनाते हुए कहा 'मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, हां मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान, तू भारत की संतान। तेरी मुट्ठियों में, बंद तूफ़ान है रे,मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, हां मनुष्य तू बड़ा महान है।'

- संवाद ब्यूरो

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत राज्य की 11 सड़कों और 11 पुलों को चौड़ा और मज़बूत करने की मंजूरी मिल गई है जिन पर करीब 725 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिविल एविएशन से संबंधित सभी प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि राज्य को उड़ान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर पहचान मिल सके।

मुख्यमंत्री सुन रहे मन

गांव-देहात की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने एवं स्थानीय लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया 'जन संवाद' कार्यक्रम खासा लोकप्रिय एवं सार्थक हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में भिवानी जिले के करीब एक दर्जन गांवों के लोगों के मन की बात सुनी। लोगों को लगा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने इतनी आत्मीयता से न केवल उनकी बात सुनी बल्कि नियम कायदों के तहत उनकी समस्याओं का समाधान भी किया।

मुख्यमंत्री ने भिवानी जिले के करीब दर्जन गांव खरक कलां, कलिंगा, चांग, तिगड़ाना, धनाना, बलियाली, बापौड़ा, दिनोद, तोशाम, दुल्हेड़ी, संडवा तथा कैरू में जन संवाद कार्यक्रम के तहत वार्ता की।

जिले के इन गांवों में कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जिनमें तीन या चार सरपंच हैं। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान महिला सरपंचों को भी इस बात का पता चला कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि की कितनी अहमियत होती है। मुख्यमंत्री ने स्वयं उनके साथ बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और गांवों की विकासपरक योजनाओं के बारे में बातचीत की।

जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष रोहतक जिले से की थी। उसके बाद उन्होंने सिरसा, सोनीपत, करनाल, कुरूक्षेत्र व फतेहाबाद जिलों में लोगों की बात सुनी। बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। जो लोग जिला मुख्यालय कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाए उनसे मुख्यमंत्री ने सीधी बातचीत की।

स्वच्छ भारत मिशन

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि स्वच्छता अभियान के तहत 135 महाग्रामों में ट्रैक्टर व ट्रॉली के माध्यम से सफाई करवाई जाएगी, जिससे जहां एक ओर लगभग 800 युवाओं को रोजगार मिलेगा तो दूसरी ओर स्वच्छ भारत-स्वच्छ हरियाणा अभियान को भी गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की पहल पर 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज बिछाने व ठोस कचरा प्रबन्धन की योजनाओं की शुरुआत की गई है जोकि गांवों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

गांवों में सैक्टर बनेंगे

शहरों की तर्ज पर गांवों में सैक्टर विकसित किये जाएंगे। इसके लिए अगर ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित कर पंचायती जमीन पर सैक्टर के लिए सहमति देती है तो सरकार उस पर तत्परता से कार्यवाही करेगी और जहां पर पंचायत की जमीन उपलब्ध नहीं है तो वहां पर ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन खरीदी जाएगी।

तोशाम में नए राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड बनाए

तोशाम में 1850 नए राशन कार्ड तथा 6339 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 197 आयुष्मान कार्डधारक अपना इलाज करवा चुके हैं, जिसकी लागत 17 लाख रुपए आई है। 'बिना पर्ची बिना खर्ची' तोशाम में लगभग 70 युवाओं को नौकरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री से संवाद करते समय लोगों ने कहा कि वर्तमान सरकार में युवा बिना किसी सिफारिश अपनी योग्यता के आधार पर नौकरियां हासिल कर रहे हैं।

मनोहर लाल ने कहा कि पहले ट्रांसफर के लिए चंडीगढ़ तक कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन वर्तमान में ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे हैं जिससे बरसों से चला आ रहा तबादला उद्योग बंद हो गया है। राज्य सरकार ने जमीन की फरद ऑनलाइन करके आम जनता को बड़ी राहत दी है। अब ऑनलाइन फरद मान्य होगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तोशाम पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत व थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। जो भी आम नागरिक थाने में अपनी शिकायत लेकर आता है, उसे गंभीरता से सुना जाए और प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने थाने को अपग्रेड करने के लिए भी ज़रूरी दिशानिर्देश दिए।

कम्प्यूटर से निकाली फरद मान्य

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि अब कंप्यूटर से निकलने वाली फरद को पटवारी से सत्यापित करवाने की जरूरत नहीं होगी। अब सीधे ऑनलाइन फ़रद ही मान्य होगी। बैंक समेत तमाम संस्थाएं ऑनलाइन फरद को मान्यता देंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास कार्य करवाने के साथ-साथ आम जन को योजनाओं व सरकारी सेवाओं का लाभ सरलता से पहुंचाने पर विशेष फोकस किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वामित्व योजना लागू करते हुए ग्रामीण परिवेश के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने का काम किया है। आज शहरी तर्ज पर गांव में विकास कार्य हो रहे हैं।

बापोड़ा के शहीदों को नमन

मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी जिले में गांव बापोड़ा में जनसंवाद कार्य' म से पहले 1965 में शहीद हुए वीर च' से सम्मानित माथन सिंह के आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री शहीद माथन सिंह के परिजनों के अलावा 1989 में श्रीलंका में शहीद हुए गिरवर सिंह, 1965 में शहीद हुए सूरजपाल, 1971 के शहीद भंवर सिंह व 2005 में शहीद हुए प्रताप सिंह के परिजनों से मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर सपूतों की कुर्बानियों के कारण ही आज सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। देश के लोगों को आपसी कटुता को भूलकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए।

माथन सिंह वर्ष 1965 की भारत-पाक की लड़ाई में शहीद हुए थे, जिन्हें वीर च' राइफल मैन के सम्मान से नवाजा गया था। उनके नाम से भिवानी का रेलवे जंक्शन बना हुआ है। बापोड़ा शहीदों और सैनिकों का गांव है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी यहीं से हैं, जो वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं।

हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा के मज़दूरों का मानदेय 331 रुपए प्रतिदिन से 26 रुपए बढ़ाकर 357 रुपए कर दिया गया है।

वर्ष 2022-23 के राज्य के अपने कर राजस्व लगभग 65 हजार करोड़ रुपए में से लगभग 3,600 करोड़ रुपए नगर निकायों को दिये जाएंगे। पिछला बकाया 500 करोड़ रुपए भी दिया जाएगा।

की बात, बिना दुभात

धनाना के 99 युवाओं को मिली नौकरी

धनाना गांव के 5582 लोगों के आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 122 लोगों ने अब तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। धनाना गांव के 1687 लोगों के नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की आयु होते ही अब बुढ़ापा पेंशन अपने आप बन रही है। इस गांव में 11 लोगों की पेंशन ऑटोमेटिक बनी है।

मनोहर लाल ने यहां आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि धनाना गांव के 36 परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, गांव धनाना के 99 युवाओं को नौकरी मिली है। ये सरकार की पारदर्शी नीति का ही परिणाम है। उनकी सरकार मैरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी दे रही है।

ई-टेंडरिंग के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई-टेंडरिंग के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता आई है और कार्यों की गति भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने धनाना ग्राम पंचायत के तीनों सरपंचों को निर्देश देते हुए कहा कि वे मिलकर गांव के विकास के लिए एक सांझी योजना तैयार करें। इसके अलावा, धनाना गांव में बस्ती में गंदे पानी की सप्लाई को 7 दिन में दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की शराब के ठेके को गांव से बाहर करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने ठेके को गांव से बाहर करने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों की लाल डोरा से संबंधित समस्या पर मुख्यमंत्री ने बताया कि धनाना गांव का 24 मार्च को नक्शा फाइनल कर दिया गया है और जल्द ही गांव को लालडोरा मुक्त कर दिया जाएगा।

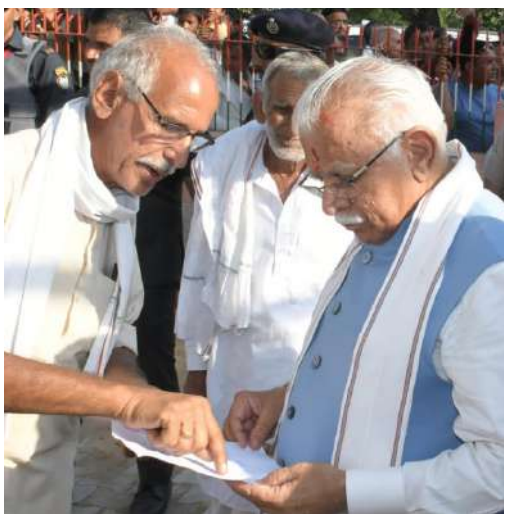

135 महाग्रामों में चलाया जाएगा सफाई अभियान

मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वच्छता अभियान के लिए देशभर में प्रेरणा का स्त्रोत बने भिवानी जिला के दूल्हेडी गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि दूल्हेडी गांव ने पूरे देश में स्वच्छता का संदेश देने का काम किया है, जिसके लिए ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मन की बात कार्य' म में दूल्हेडी गांव की स्वच्छता अभियान के लिए प्रशंसा कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 135 बड़े गांवों में स्वच्छता अभियान के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली दी जाएंगी और जरूरत अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने भिवानी के उपायुक्त व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भिवानी जिले में ढुल्लेडी मॉडल के आधार पर गांव के अंदर सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिस गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, वहां 1- 2 एकड़ भूमि के अंदर गांव के कूड़े कचरे को इकट्ठा कर कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। इस खाद को बेचकर गांव की पंचायत की आमदनी बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने दूल्हेडी गांव की युवा स्वच्छता जन सेवा समिति को गांव की सफाई के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की।

निकायों को पूर्ण स्वायत्तता देने की प्रतिबद्धता

प्रदेश सरकार नगर निकायों को पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्य समयबद्ध और अविलंब हो सकें। वर्ष 2022-23 के राज्य के अपने कर राजस्व (एसओटीआर) लगभग 65 हजार करोड़ रुपए में से लगभग 3600 करोड़ रुपए नगर निकायों को दिये जाएंगे। इसके अलावा पिछला बकाया 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस प्रकार 4100 करोड़ रुपए नगर निकायों को मिलेंगे, जिससे वे अपने स्तर पर विकास कार्य करवा पाएंगे। सभी निकायों में कुल मिलाकर 5 हजार करोड़ रुपए की राशि पहले से ही उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगमों के महापौरों और जिला नगर आयुक्तों के साथ शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 21 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का प्रावधान किया जाए।

नई कालोनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा: भविष्य में अब नई अवैध कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। पहले से बनी कॉलोनियों, जिनमें कुछ हिस्से या पैच को अनियमित दिखाया हुआ है, उन्हें तय मानदंड अनुसार नियमित किया जाए। सीएम ने कहा कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने 190 कॉलोनियों को अप्रूव किया है। इसके अलावा, लगभग 600-700 कॉलोनियां पाइपलाइन में हैं।

व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम किए

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 साल में राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के कई काम किए हैं। सरकार का प्रयास है कि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिले। इसके लिए हर क्षेत्र में पारदर्शिता बरती जा रही है।

मुख्यमंत्री गांव बलियाली में जन संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा पूरा हरियाणा उनका परिवार है और वे परिवार के मुखिया के नाते अपने परिवार के हर सदस्य को सहयोग देने के लिए सजग हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में विकास कार्यों पर पूरा फोकस किया गया है और किसी भी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में धन की कमी नहीं आने दी जा रही है।

मनोहर लाल ने कहा कि पूरी निष्पक्षता के साथ सरकार द्वारा जनहितकारी नीतियों को लागू करते हुए आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि वे लोग पूर्व की सरकारों के कार्यकाल व मौजूदा सरकार के कार्यकाल की तुलना करके देखें, फर्क साफ नजर आएगा कि जितना आधारभूत ढांचागत विकास मौजूदा सरकार में हुआ है, उतना किसी भी पूर्व की सरकारों में नहीं हुआ।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग अनुरूप प्रदेश के सभी खालों व माइनर के नवीनीकरण व सुधारीकरण के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने ग्रामीणों की सामूहिक समस्याओं को सुना और समाधान के लिए सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 21 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने के निर्देश दिए हैं।

जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।

ख़राब फसलों का मिलेगा मुआवज़ा

पूरे हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर हुई बेमौसमी बरसात एवं ओलावृष्टि के कारण फसलों में कम या ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे किसानों को ख़ासा नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसे में प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा जैसी हर परिस्थिति में किसानों के साथ हर संभव सहयोग के लिए खड़ी है। फसलों का मुआवज़ा सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी करवाते हुए मई माह तक दिया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे फसलों का सटीक एवं सही आंकलन करके ही नुकसान की रिपोर्ट भेजें, ताकि संबंधित किसानों को ज़ल्द से ज़ल्द मुआवज़ा दिलवाया जा सके। 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल किसानों की सुविधा के लिए है और किसान अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करवाकर लाभ उठा सकते हैं।

किसानों के साथ खड़ी है सरकार : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसानों का किसी भी प्रकार का यदि नुकसान होता है तो राज्य सरकार त्वरित मुआवज़ा देती है। हमने वर्ष 2015 में ही 1,200 करोड़ रुपए का मुआवज़ा दिया था। वर्तमान सरकार ने 1,300 करोड़ रुपए का मुआवज़ा किसानों को दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने नुकसान का ब्यौरा भरना अनिवार्य है। इसके अलावा, जो किसान स्वयं क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का आकलन नहीं भर सकते वे कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भरवा सकते हैं। सरकार द्वारा उसका खर्च वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसल का बीमा करवाने वाले किसानों को कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है और बीमा न करने वाले किसानों को सरकार द्वारा 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया: मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसको देखकर लगता है कि सरकार को मुआवज़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन हम किसान को नुकसान बर्दाश्त नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि 'मेरी फसल - मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर किसानों द्वारा अपने ज़मीन का क्षेत्र व फसल का की पूरी जानकारी दर्ज़ करवाई जाती है। अब तो सरकार ने ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल भी बनाया है, जिस पर 72 घंटे के अंदर किसान अपनी फसल का ख़राबा दर्ज़ करते हैं। सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चल रही है और मई माह तक सभी किसानों को मुआवज़ा वितरित कर दिया जाएगा।

फसल मुआवज़े में पारदर्शी व्यवस्था: बनवारी

सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने फसल क्षतिपूर्ति प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाया है और पोर्टल से किसान की फसल के नुकसान का सही आकलन होता है। जनस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फसलों में हुई क्षति से किसानों को राहत देने के लिए ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पुनः खोला गया है। जिन किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है, वे अपनी फसल का ख़राबा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आसानी से अपलोड कर सकते हैं। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाया हुआ है, उन्हें सम्बंधित बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा दिलवाया जाएगा। जो किसान किसी कारण फसलों का बीमा नहीं करवा पाए हैं, उनके नुक्सान की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी।

भरपाई करेगी सरकार: चौटाला: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी करवाकर जिलावार रिव्यू करने के निर्देश दे दिए गए हैं और रिपोर्ट आने पर किसानों को फसल ख़राबे की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे किसान जिनको गत समय में बरसात व ओलावृष्टि की एवज में सरकार द्वारा मंजूर किया मुआवज़ा अभी तक नहीं मिला है तो वे अपना खाता व फ़र्द का मिलान करवा लें, फिर भी कोई परेशानी आती है तो संबंधित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन संबंधित एसडीएम को दें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रभावित किसान को फसल ख़राबे का मुआवज़ा दिया जाएगा, इसके लिए चाहे विभाग द्वारा गांव-गांव कैंप ही क्यूं ना लगाने पड़े।

किसान बने इंजीनियर

पानी पूरी विद गन्ना जूस की नई पहल

संगीता शर्मा

हरियाणा के किसान अब हाईटेक हो चुके हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं। किसानों ने गन्ने के उत्पाद बनाकर उसकी मार्केटिंग करने के लिए करनाल में 'सेलीब्रेटिंग हरियाणा हट' नाम से दुकान खोली है। इतना ही नहीं, बल्कि किसानों ने अपनी मेहनत, लगन व इनोवेशन से कार्ट तैयार की है। 'मेरा गन्ना- मेरी मशीन' के तहत किसानों ने कार्ट व मशीनें बनाई हैं और अन्य किसानों को भी इसको बनाने के गुर सीखा रहे हैं ताकि वह इस क्षेत्र में नया कर सकें। सेलीब्रेटिंग फार्मर्स एज इंटरेनशनल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विपन सरीन की देखरेख व उचित मार्गदर्शन में कार्य की शुरुआत की गई है। किसानों ने पानी पूरी विद गन्ना जूस व चटनी के साथ सर्व करने की पहल की है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हितकारी है।

आमदनी में बढ़ोतरी

करनाल के हरियाणा हट आउटलेट में बीस किसानों ने मिलकर गन्ने के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। किसान मनदीप के घर के नीचे दुकान है और उनको 5,000 रुपए मासिक किराया देते हैं। इससे किसान की भी आमदनी हो रही हैं। प्रगतिशील किसान शिव सेहरावत ने बताया कि हिसार यूनिवर्सिटी के इनक्यूबेशन सेंटर में विपन सरीन इनक्यूबेटर हैं और उन्होंने कार्ट तैयार करवाने का उचित मार्गदर्शन लिया। इस प्रोजेक्ट में विपन सरीन, शिव सेहरावत, जोगेश मलिक, मनदीप पहल, मनमोहन सिंह, हरभजन सिंह, बिजेंद्र सिंह, जयपाल आर्य, जगबीर आर्य, ज्ञान आर्य, राकेश आर्य, राजेश, बलराम, विजय, जोगेंद्र, सरजीत सिंह, शलैंद्र बेनीवाल, नरेंद्र, अनिल बिश्नोई, विनोद कुमार शामिल हैं। पलवल, पानीपत, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, गोहाना, जींद, हिसार, झज्जर, रतिया में कार्ट का संचालन किया जा रहा है।

इनोवेशन

'मेरा गन्ना- मेरी मशीन' प्रोजेक्ट के तहत ट्रैक्टर के पीछे चलने वाली कार्ट, जूस निकालने वाली मशीन, गन्ने को छिलने वाली मशीन व गन्ने का छिलका साफ करने वाली पिलिंग मशीन बना चुके हैं, जिसका किसानों को अधिक फ़ायदा मिल रहा है। अब अगले महीने तक किसान मिलकर एडवांस लेवल के पांच रोलर वाली जूस मशीन डवलेप कर रहे हैं। यह तीन रोलर वाली मशीन से अधिक असरदार होगी। इसके अतिरिक्त 150 लिटर की कढ़ाई यानि टिल्टिड पेन बनाई है। बॉयलर में गुड़ वाली 150 लिटर की कढ़ाई को किसान आसानी से दूसरे बर्तन में खाली कर सकता है। इसके अतिरिक्त स्टीम मेकर एक कंपनी के सहयोग से तैयार कर रहे हैं। जिस काम को करने पर चार से पांच घंटे लगते थे अब स्टीम मेकर से 30-40 मिनट लगेंगे। चुस्की, केक व अन्य फ्रोजन आइटम्स इसमें बनाएं जा सकेंगे। इसमें युवा सोच प्रिंस किसानों के लिए प्रेरणा स्त्रोत है, जिन्होंने इनोवेशन करने में मदद की है। जींद के किसान राजेश ने कार्ट तैयार की है। किसानों ने गन्ने जूस निकालने की मशीन बनाई है जिसकी बाज़ार में कीमत 70,000 रुपए से 80,000 रुपए हैं जबकि किसानों ने 40,000 रुपए की कीमत में इसे तैयार किया है। बाइक के पीछे ट्रेक्टर ट्राली लगाकर कार्ट तैयार की गई है। जल्द ही वे ई कार्ट भी तैयार करेंगे।

गन्ना उत्पादों से मुनाफ़ा

पलवल के किसान शिव सेहरावत ने बताया कि 300 किसानों को गन्ना खेती करने व गन्ने के उत्पाद तैयार करके बेचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। किसानों द्वारा फार्मर इंटररेस्ट ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जिसमें दस से बीस किसान होते हैं। इनमें चार एफआईजी के 50 सदस्य पूरी लगन व मेहनत के गन्ने के उत्पाद बनाकर उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं और इससे मुनाफ़ा कमा रहे हैं। किसान गन्ने की चुश्की, गन्ने -इमली चटनी, फ्रोजन जूस, गन्ने की चाय व काफी आदि अन्य उत्पाद तैयार करते हैं। गन्ने की खेती जैविक करते हैं। जींद के राजेश गन्ने के उत्पाद बनाकर मार्केटिंग कर रहे हैं और उन्होंने बाइक ट्रॉली कार्ट को डिजाइन किया व बनाया है। इसमें डिप फ्रीज, स्टोरेज के प्रोडक्ट, फ्रोजन जूस व इंडक्शन भी रखा गया है और इसमें चाय व कॉफी बनाकर बेची जा रही है। गोलगप्पे के लिए गन्ने का पानी किसानों ने तैयार किया हैं। यह अधिक स्वादिष्ट व नया फ्लेवर है। शिव कुमार ने बताया कि दो कार्ट तैयार की है और इसमें सोलर एनर्जी का प्रयोग किया है। गोहाना के योगेश मलिक ने दो ट्रेक्टर ट्रॉली कार्ट तैयार किए है और इसमें से एक कार्ट रोहतक में और एक कार्ट यूपी में भेजी गई है। उन्होंने बताया कि इस समय 6,000 रुपए से 8,000 रुपए के गन्ने के उत्पादों की बिक्री प्रतिदिन होती है और आने वाले समय में 8,000 रुपए से 10,000 रुपए की बिक्री होने की संभावना है।

पानी पूरी विद गन्ना जूस

पानीपत के युवा किसान बिजेंद्र ने अपना गन्ने के उत्पादों का पहला आउटलेट पानीपत में शुरू किया है और उन्होंने पानी पूरी विद गन्ना जूस का स्वाद चखा। उनका कहना है कि गन्ना जूस व इमली के साथ गोलगप्पे का पानी बनाया गया है और यह बहुत स्वादिष्ट है। ज्योति का कहना है कि फास्टफूड हमारी सेहत को ख़राब करता है, जबकि यह पानी पेट के लिए अच्छा होता है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया कॉफ़ी टेबल बुक को रिलीज़ किया जो डॉक्टर प्रभलीन द्वारा लिखी गई है।

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत 14,409 प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु मिड डे मील बजट में 58 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 661 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

आतिथ्य सत्कार से जीता विदेशी मेहमानों का दिल

जी-20 के प्रतिनिधियों के लिए शानदार कार्यक्रम

हरियाणा सरकार ने कला-संस्कृति, खान-पान और आतिथ्य सत्कार से जी-20 बैठकों में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों का दिल जीत लिया। पिंजौर के ऐतिहासिक यादवेंद्र गार्डन में सरकार की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विदेशी मेहमानों को हरियाणा व देश की संस्कृति से रूबरू कराया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी दलाल और विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्य म में शिरकत की। गार्डन में पहुंचे प्रतिनिधियों को भारत की अतिथि देवो भवः और वसुधैव कुटुंबकम् की परंपरा और समृद्ध कला संस्कृति से रूबरू कराने के लिए यह आयोजन किया गया है।

रात्रि के समय यादवेंद्र गार्डन रंग -बिरंगी रोशनी से सराबोर नज़र आया, जो माहौल को और खुशनुमा और ख़ास बना रहा था। विदेशी मेहमानों के आगमन पर मुख्य गेट पर पारंपरिक परिधान पहने हरियाणवी कलाकार ढोल-नगाड़े बजाकर उनका अभिनंदन कर रहे थे। इसके बाद, मेहमानों को तिलक लगाकर व पारंपरिक लोक गीत गाकर स्वागत किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। प्रदेश में विभिन्न त्योहार व अन्य अवसरों जुड़े पारंपरिक लोक नृत्यों लूर, घूमर, धमाल, फाग, फाल्गुन आदि की प्रस्तुति देते हुए हरियाणवी लोक शैली का प्रभावी रूप से प्रदर्शन किया। इससे विदेशी मेहमानों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। विदेशी मेहमानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी दलाल, विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समूह चित्र भी खिंचवाए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल और अन्य अतिथियों ने गार्डन का भ्रमण किया और जी -20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अनूठे अंदाज में नज़र आए। उन्होंने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने कलाकरों से भी बातचीत की और उनकी हौसला अफज़ाई की। वे छोटे बच्चों के साथ भी खुशनुमा मूड में नज़र आए। उन्होंने ढोल-नगाड़े बजाने वाले कलाकारों के साथ मिलकर ढोल भी बजाया, जिससे कलाकार भी और अधिक जोश व उत्साहित हो उठे।

कार्यक्रम के दौरान विदेशी मेहमानों को प्रमुख महत्व वाले स्थानों, कला-संस्कृति, खान-पान आदि विविध पहलुओं से रूबरू कराया गया। रात्रिभोज पर अलग-अलग क्यूज़ीन के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर के तहत मोटे अनाज से तैयार व्यंजन भी परोसे गए।

- संवाद ब्यूरो

खेल सुविधाओं में होगा इजाफ़ा, जल्द भरेंगे पद

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के खिलाड़ियों के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन को देखते हुए अधिकारी हर प्रकार की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए बजट में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के रख-रखाव के लिए आवश्यकतानुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्मय से ग्राऊंडमैन व अन्य पदों को शीघ्र भरें।

उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक खिलाड़ी, चाहे वह पदक विजेता है या किसी खेल में प्रतिभागी रहा है, उसकी पूरी जानकारी परिवार पहचान पत्र में उपलब्ध हो। कई योजनाओं का लाभ देने के लिए यह डाटा काफ़ी कारगर रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के पारम्परिक खेल जैसेकि कुश्ती, कबड्डी के लिए खेल प्रतिभाओं को तराशने वाले अखाड़ों संचालकों को भी सम्मानित करने की भी कोई योजना बनाई जाए। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अपने बजट अभिभाषण में कुश्ती जगत में अखाड़ा संचालन में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले मास्टर चंदगी राम के नाम से खिलाड़ियों के लिए ''स्पोर्टस पर्सन इंशयोरेंस बेनिफिट स्कीम'' की घोषणा भी की है।

खेल विभाग का बढ़ा बजटः खेल निदेशक पंकज नैन ने अवगत करवाया कि पंचकूला, फरीदाबाद व रोहतक में तीन राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला खेल परिसर, 25 उप-मंडलीय स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामी खेल परिसर तथा 245 गांवों में लघु /ग्रामीण खेल स्टेडियम हैं। विभाग का प्रयास है कि उभरते खिलाड़ियों को खेल की प्रकृति के अनुरूप खेल सुविधाएं उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल इन्फ्रास्ट्र• र का रख-रखाव भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम। विभाग की ओर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर 202 जूनियर कोच, 254 ग्रांऊडमैन तथा 203 चौकीदार-सह-माली-सह-सफाई कर्मचारी भरने का प्रस्ताव है। हरियाणा पंचकूला में स्थापित की जा रही खेल अकादमी के लिए भी एक प्रबंधक, आठ प्रमुख कोच, तीन खेल फिजियोथेरेपिस्ट, एक डाईटिशियन तथा एक साइकोलॉजिस्ट की भी मांग भेजी गई है। वर्ष 2023-24 के लिए खेल विभाग का बजट 540.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 566.04 करोड़ रुपए किया गया है।

उत्कृ ष्ट खिलाड़ियों को दी गई 179 नियुक्तियांः वर्ष 2023 तक 216 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति के लिए पेशकश की गई जिनमें से 179 खिलाड़ियों ने ज्वाइन किया है जबकि 2013-14 में केवल 41 खिलाड़ियों को ही नौकरी दी गई थी। राज्य में 1100 खेल नर्सरियां संचालित हैं। खेल नर्सरी योजना को नए सिरे से अवधारित कर शैक्षणिक संस्थानों में हस्तांतरित किया जा रहा है। इसके लिए विभाग सरकारी व निजी संस्थानों से समन्वय स्थापित कर रहा है। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को हर वर्ष खेल उपकरण व खेल इन्फ्रास्ट्र• र पर खर्च करने के लिए तीन लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि उभरते खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा का युवावस्था में ही पता लगाया जा सकें। इसके अलावा, 24 आवासीय अकादमियां खोलने का भी प्रस्ताव है जिनमें 600 एथलीट, 12 खेलों की सुविधाएं दी जाएंगी। इन आवासीय अकादमियों में प्रत्येक खिलाड़ी को 400 रुपए प्रतिदिन खुराक भत्ता दिया जाएगा।

महिला खिलाड़ियों को नकद ईनाम और नौकरी का प्रस्ताव

जीवन में कितनी ही मुश्किलें आए या फिर लगातार हार का सामना क्यों न करना पड़े। ऐसे में युवा का धैर्य, बुलंद हौसले व उचित मार्गदर्शन उन्हें सफलता की नई ऊंचाईयों पर ले जाता है। कुछ ऐसी कहानी है हरियाणा की युवा मुक्केबाज नीतू घणघस व स्वीटी बूरा की। इन बेटियों ने एक बार फिर से खेलों में अपने दमखम का परिचय देते हुए नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित आईबीए महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है।

हरियाणा की दोनों मुक्केबाज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ स्थित अपने संत कबीर कुटीर आवास पर एक कार्यक्रम में दोनों खिलाड़ियों को 40-40 लाख रुपए का चैक तथा हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम के अंतर्गत ग्रुप बी की नौकरी का ऑफर लेटर की पेशकश भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार खेलों के प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाओं को लागू कर रही है। करोड़ों रुपए के नगद पुरस्कार के साथ-साथ खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रही है। सरकार की नई खेल नीति के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं और हमारे बेटे व बेटियां लगातार जीत का परचम लहरा रही हैं।

पिता ने निभाई विशेष भूमिका

भिवानी में जन्मी नीतू घणघस ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की वांग लीना को कड़े मुकाबले में 4-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वह न्यूनतम भार वर्ग में 2023 विश्व चैंपियन हैं और हल्के फ्लाईवेट में दो बार की विश्व युवा चैंपियन हैं। उन्होंने 2023 विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में न्यूनतम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नीतू का जन्म 19 अक्तूबर, 2000 को हरियाणा के भिवानी के धनाना गांव में हुआ था। उनके पिता जय भगवान, चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य सभा में कर्मचारी थे और मां का नाम मुकेश देवी है। उसके पिता ने नीतू को बॉक्सिंग से परिचित कराया।

पति ने प्रोत्साहित किया

मुक्केबाज स्वीटी बूरा ने 81 किलो भारवर्ग में स्वर्णिम सफलता हासिल की। बूरा ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से मुक्केबाजी की दुनिया में अपना नाम बनाया है। हिसार की स्वीटी ने एक समय हताश होकर मुक्केबाजी खेलना छोड़ दिया था और कबड्डी खेलना शुरू किया लेकिन पति दीपक निवास हुड्डा जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं ने इन्हें मुक्केबाजी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और दोबारा गलब्स पहने और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका जन्म 10 जनवरी 1993 को हिसार में हुआ।

स्वीटी ने बताया कि उन्हें मुक्केबाजी में करियर बनाने के लिए उनके पति दीपक निवास हुड्डा ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने ही एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ट्रायल देने के लिए कहा, जिसके बाद स्वीटी ने ट्रायल दिया और भारतीय टीम में इनका चयन हो गया। स्वीटी हरियाणा पुलिस विभाग में एक पुलिस अधिकारी हैं। वह 2019 में एक कांस्टेबल के रूप में पुलिस बल में शामिल हुईं और तब से एक बॉक्सर और एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने करियर को संतुलित कर रही हैं

- संगीता शर्मा

> राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में खेलों के लिए अनुकूल माहौल बने और खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इसके साथ- साथ उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोचिंग की सुविधाएं भी मिलें ताकि वे खेलों में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें।
>
> **मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा**

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि रहबरे आजम चौधरी छोटूराम वास्तव में किसान एवं कमेरे वर्ग के मसीहा थे। उन्होंने हमेशा दिशाहीन एवं कमजोर व्यक्ति के हित की लड़ाई लड़ी।

शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा के लिए 'जीरो ड्रॉप आउट' नीति पर काम किया जा रहा है ताकि अगले वर्ष तक प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे।

कुरुक्षेत्र में सांग महोत्सव

हरियाणा की माटी के कण-कण में संस्कृति का वासः डॉ. अग्रवाल

सांग विद्या प्रदेश की संस्कृति और विरासत का अटूट अंग है। इस प्रदेश की संस्कृति को समृद्ध बनाने में सांग जैसी विद्याओं का अहम योगदान है। इसलिए इस संस्कृति को सहेजने और इसके संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। आने वाले समय में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने कुरुक्षेत्र में हरियाणा कला परिषद के सभागार में आयोजित पांच दिवसीय सांग महोत्सव में यह कहा। आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित धनपत सिंह सांगी की स्मृति में आयोजित महोत्सव में उन्होंने महान सांगी धनपत सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से सांग महोत्सव का शुभारंभ किया।

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति समृद्ध संस्कृति है, इस प्रदेश की माटी के कण-कण में संस्कृति का वास है। सांग यहां की प्राचीन एवं परम्परागत विद्या है। इस विद्या से हरियाणा प्रदेश की संस्कृति का अटूट और अनोखा संबंध है।

उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को एक बड़ा स्वरूप देने का कार्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया। इस गीता स्थली की धरा पर आज से 5 हजार वर्ष पूर्व भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए जो आज भी पूरे विश्व के लिए पूर्णतया प्रासंगिक है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन मॉरीशिस, लंदन, कनाडा में किया जा चुका है। गौरतलब है कि 28 से 30 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विकास बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के कलाकारों को आजीवन पेंशन देने की योजना है।

-संवाद ब्यूरो

सुण छबीले बोल रसीले

बैठणा भाइयां का, चाहे बैर क्यूं ना हो

छबीले, काल एक भाई का फोन आया, बहुत परेशान था, बोल्या- छबीले चाळा होग्या, बरबाद होग्या। कितोड़ मुंह दिखाण जोगा कोन्या रहा।

मनै पूछ्या अरै न्यू तो बता, बात के होई ?

बोल्या, भाई छबीले, के बताऊं, बताती हाणा शर्म आवै सै। पर तेरे आगै न्यू बताऊं सूं अक कुछ समाधान होज्या ।

- अरै भाई कुछ होया भी होगा, कुछ बात तो बता ?

बोल्या- छोरी दिल्ली में अफसर बणन खातिर पढ़ाई कर्‌या करती। उसनै एक छोरे गेल्यां लव मैरिज कर ली। ईब न्यू बता हाम के कर सकैं सैं?

- मनैं बताई कि भाई थाम कुछ नहीं कर सकते। जै वे बालक बालिग सैं तो कानूनी हिसाब तैं कोई कुछ नहीं कर सकता। थाम आपणे दिल नै समझाओ और बिना परेशान हुए आराम तैं आपणी जिंदगी बीताओ। उननै जो करणा था कर लिया और जो आगै चाहवैंगे कर लेंगे। हां फेर कहूं सूं कानूनी हिसाब तैं थाम कुछ नहीं कर सकते। हां में हां और ना में ना कर सको सो।

- छबीले, होया तो गलत। ईसा नहीं होणा चाहिए।

-भाई रसीले, कानून नै के उन ताहीं न्यू कही थी अक थाम घर तैं भाजकै लव मैरिज कर ल्यो। गए तो वे आपणी मर्जी से हैं। इसमें कानून का कोई खोट कोन्या। कानून तो न्यू कहै सै अक बालिग हो चुके बालक समझदार होज्या सैं, वे आपणी मर्जी के मालिक सैं, वे आपणी जिंदगी के बारे में कोई भी फैसला लेणे के लिए आजाद सैं।

- छबीले, यो समझदारी कोन्या होती, यो पागलपन हो सै। समझैंगे, पर जिब समझैंगे जिब टाइम जा लिया होगा। इस तरियां के रिश्ते बहुत कम निभै सैं। कदे हो जूत बाज जाया करै।

मैं न्यू नहीं कहता अक दूसरी जात बिरादरी की वजह तैं टूटै सैं। सफल भी हो सैं। पर ज्यादातर टूटैं सै, बिना मां बाप की सलाह लिए तैं। उम्र के झोक में बालक गलत कदम ठा ले सैं। वे उस टैम पै ना तो आपणे भविष्य की चिंता करते और ना आपणे मां-बाप व खानदान की इज्ज़त का ख्याल राखते। बहक ज्यां सैं और फेर सारी जिंदगी परेशान रहैं सैं।

- हां भाई रसीले, किसे मां-बाप नै आपणी औलाद भूंडी कोन्या लागती। सब न्यू चाहवैं सैं अक उनके बालक खूब कमावैं और मौज तैं रहवैं। इस तरियां के केस में बालकां नै चाहिए अक जै किते आपणे लेवल पै बात चालरी सै तो मां-बाप नै या भाई बहन नै विश्वास में लें। दोनों तरफ के परिजन राजी होज्यां तो रिश्ता करल्यो। ना राजी सैं तो कतई टाल मारो। फेर उस तरफ देखणा भी नहीं चाहिए।

- छबीले, हर बालक नैं चाहे वो छोरी हो या छोरा, आपणे मां बाप की इज्जत का ख्याल पहल्यां राखणा चाहिए। जो औलाद आपणे मां-बाप नै खुश नहीं राख सकती उस औलाद का कोई सुख कोन्या। म्हारे समाज में परिवार को बोहत पवित्र और ऊंचा स्थान मान्या गया सै। जीवन के लिए सामाजिक ताना-बाना, रीति-रिवाज बहुत जरूरी सै।

- माड़ी बात तब हो सै रसीले जिब लव मैरिज करण आले जातक-जातकियां का घर परिवार तैं सदा सदा के लिए नाता टूटज्या सै। घर परिवार बिना कोई जीणा कोन्या होता। न्यू कहा करैं, बैठणा भाइयां का चाहे बैर क्यूं ना हो। और न्यू भी कहा करैं- जातकी, पीहर के भुहाड़े में सासरै और सासरे के भुहाड़े में पीहर में मौज मार्‌या करै। और किसे कै आगे पाछै कोई परिवार ना हो तो रे-रे माटी होज्या सै। बदनामी होवै वो अलग।

- छबीले, बोहत माड़ा टैम आग्या। आजकाल के बालक ब्याह शादी नै बेरा ना के समझै सैं। चिंता की बात इसलिए भी सै अक पढ़े-लिखे बालकां में भी यो बिमारी देखी जा री सै।

- मैं तो एक बात जाणूं सूं रसीले, जिंदगी में ब्याह शादी कोई उपलब्धि कोन्या। यो तो कदे कर ले। उपलब्धि मानी जा सै जिंदगी में कुछ बणन की, कुछ इसा बढ़िया काम करण की अक मां-बाप का, पूरे खानदान का, गांव, शहर व देश-प्रदेश का नाम ऊंचा हो। पढ़ाई लिखाई, खेल, उद्योग और अनेक तरियां के क्षेत्रां में कुछ नया करण के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार पूरा सहयोग दे री सै। युवाओं नै सरकार की योजनाओं का फायदा उठाणा चाहिए।

- छबीले, ईब तो खेती बाड़ी का क्षेत्र भी घाटे का काम ना रहा। बीज तै लेकै फसल बिकणे तक सरकार जोखिम में किसान के साथ खड़ी सै। यानी फायदा होगा तो किसान का और नुकसान होया तो सरकार सहयोग करैगी।

- रसीले, कुल मिलाकै बात यो सै अक जवान जातक जातकियां नैं खुशहाल जीवन जीने के लिए खूब कड़ी मेहनत करणी चाहिए। ब्याह शादी के चक्कर में ना पड़कै सफल आदमी बणना जरूरी है। कुछ भी इसा गलत कदम ना उठावैं जिस तैं समाज में मां-बाप की गर्दन नीची हो।

-मनोज प्रभाकर

नमन है भीमराव को

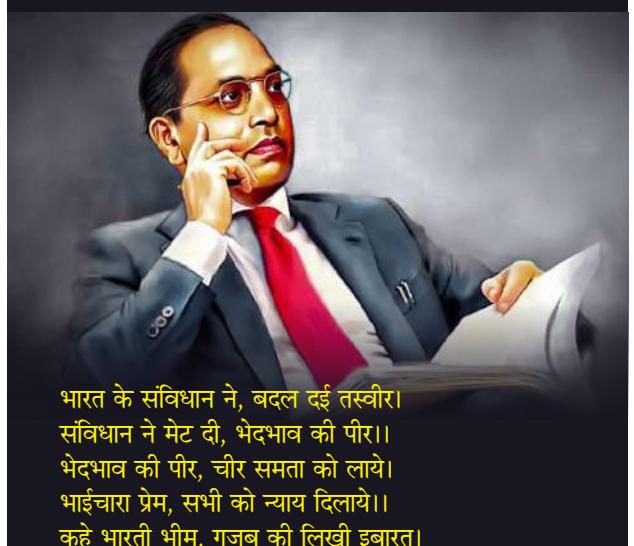

भारत के संविधान ने, बदल दई तस्वीर।
संविधान ने मेट दी, भेदभाव की पीर।।
भेदभाव की पीर, चीर समता को लाये।
भाईचारा प्रेम, सभी को न्याय दिलाये।।
कहे भारती भीम, गजब की लिखी इबारत।
न्यारा प्यारा देश, अपना गणतंत्र भारत।।

भीम चलाई लेखनी, रच दिया संविधान।
सारी तोड़ी बेड़ियां, लाये नया विहान।।
लाये नया विहान, दूर करा अंधियारा।
आया है गणतंत्र, लिए समता उजियारा।।
देश बणा गणतंत्र,भीम ने करी सहाई।
शोषण मेटा देख, लेखनी भीम चलाई।।

भाईचारा प्रेम का, शामिल भाव महान।
न्याय समता स्वतंत्रता, दे हमें संविधान।।
दे हमें संविधान, ज्ञान का पाठ पढ़ाया।
मौका मिले समान, मान भी ख़ूब बढ़ाया।।
बना भारती देश, धर्म निरपेक्ष हमारा।
जाति धर्म को छोड़, निभाओ भाईचारा।।

नमन है भीमराव को, कलम थमाई हाथ।
बदलेंगे तकदीर को, सबको लेकर साथ।।
सबको लेकर साथ, भीम की राह चलेंगे।
झुके नहीं ये माथ, सभी संघर्ष करेंगे।।
करो भारती ख़ूब, देश पर अर्पण तन मन।
भीमराव को कलम, करे सदा सादर नमन।।

- भूप सिंह भारती

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com